दैनिक भारत कि
तामीर
संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com
Editor in chief- Qazi makhdoom shafiuddin
बीड (महाराष्ट्र) वर्ष-१ ला अंक-२९३ वा शुक्रवार २३ मे २०२५ RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 किमत : २ रूपये पन्ने - ४

'खोखले भाषण देना बंद करें' राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, तीन तीखे सवाल पूछे

- नई दिल्ली, २२ मई

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए उनसे तीन सीधे सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट कर कहा कि मोदी जी, खोखले भाषण देना बंद कीजिए।

यह प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी का दिमाग ठंडा है, लेकिन खून गर्म है। मेरी रगों में गरम सिंदूर बह रहा है। प्रधानमंत्री मोदी बिकानेर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि २२ अप्रैल को हुए आतंकी हमले का बदला हमारी सेना ने २२ मिनट में ले लिया। पाकिस्तान और आतंकवादियों ने देख लिया है कि जब सिंदूर बारूद में बदलता है, तब क्या होता है। प्रधानमंत्री के इस बयान पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने शाम को पोस्ट किया और तीन सवालों के साथ प्रधानमंत्री से जवाब मांगा:

१. आपने आतंकवाद पर पाकिस्तान की बातों पर विश्वास क्यों किया?

२. आपने ट्रंप के सामने झुककर भारत के हितों की बलि क्यों दी?

३. आपका खून केवल कैमरों के सामने ही क्यों उबलता है? क्या आपने भारत की गरिमा से समझौता किया है?

राहुल गांधी के इन सवालों से एक बार फिर चुनावी माहौल गर्म हो गया है और दोनों दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है।

अकरावी प्रवेश प्रक्रिया में तकनीकी खामी से छात्रों और पालकों को मनस्ताप, वेबसाइट चार दिन तक बंद रहेगी

जमीर काजी

। मुंबई । २२ मई २०२५

राज्य शिक्षा मंडल द्वारा ११वीं कक्षा (अकरावी) के लिए शुरू की गई ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में तकनीकी अड़चनों के चलते छात्रों और अभिभावकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले यह प्रक्रिया २१ मई से शुरू होनी थी, लेकिन पोर्टल में तकनीकी दिक्कतें आने के कारण इसे अब २६ मई २०२५ से शुरू किया जाएगा।

नया शेड्यूल घोषित:

राज्य शिक्षा संचालनालय ने नया समय-सारणी घोषित करते हुए बताया कि अकरावी प्रवेश की ऑनलाइन प्रक्रिया अब २६ मई से ३ जून तक चलेगी। उसके बाद, ५ जून को पहली जनरल मेरिट लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। छात्रों को यदि कोई आपत्ति हो तो वे ६ और ७ जून को शिकायत दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद ८ जून को अंतिम मेरिट सूची जारी की जाएगी, जबकि पहली गुणवत्ता सूची १० जून को घोषित की जाएगी।

तकनीकी कारणों से वेबसाइट ४ दिन बंद:

शिक्षा मंडल के अनुसार, वेबसाइट को मोबाइल यूज़र्स के लिए अधिक सहज और प्रभावी बनाने के लिए अगले चार दिनों तक पोर्टल बंद रहेगा। पहले यह सुविधा २१ मई से २८ मई तक उपलब्ध होने वाली थी, लेकिन तकनीकी गड़बड़ियों के कारण उसे रद्द कर दिया गया है।

व्हॉट्सऐप चैनल से दी जाएगी जानकारी:

शिक्षा मंडल ने यह भी बताया है कि छात्रों और पालकों को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही वेबसाइट दोबारा शुरू होगी, एक विशेष व्हॉट्सऐप चैनल के माध्यम से सभी छात्रों को प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी तत्काल दी जाएगी।

पहली बार राज्यभर में एक समान ऑनलाइन प्रणाली:

इस वर्ष पहली बार अकरावी की प्रवेश प्रक्रिया राज्यभर में एक समान ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से लागू की गई है। इससे छात्रों को एक ही आवेदन पत्र के जरिए राज्य के किसी भी कॉलेज में प्रवेश लेने का विकल्प मिल रहा है। लेकिन प्रक्रिया के पहले ही दिन वेबसाइट पर आई तकनीकी दिक्कतों ने छात्रों को असुविधा में डाल दिया है।

शिक्षा संचालनालय का कहना है कि प्रवेश प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक तकनीकी सुधार किए जा रहे हैं और छात्रों को समय पर हर सुविधा दी जाएगी।

एसपी नवनीत कॉवत की सख्ती: बीड जिले में ६०६ पुलिसकर्मियों का तबादला, 'गॉडफादर' की सिफारिशें नहीं चलीं

बीड, २२ मई: बीड जिले में वर्षों से नेताओं और रसूखदारों के आशीर्वाद से एक ही स्थान पर टिके रहने वाले पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर एसपी नवनीत कॉवत ने कड़ा एक्शन लेते हुए बड़ा तबादला अभियान चलाया है। गुरुवार (२२ मई) को पुलिस अधीक्षक ने ६०६ पुलिसकर्मियों के तबादले किए, जो अब तक का सबसे बड़ा और पारदर्शी तबादला माने जा रहा है।

यह पहली बार हुआ है जब न तो किसी नेता की सिफारिश चली, और न ही कोई लेन-देन का खेल हुआ। बिना किसी वशिलेबाजी या पैसे के, केवल योग्यता और नियमों के आधार पर ये तबादले किए गए हैं। इस निर्णय से कई पुलिसकर्मियों को झटका भी लगा है, वहीं आम जनता और विभाग में एसपी की पारदर्शिता की सराहना हो रही है।

कड़ी चेतावनी के बाद भी नहीं माने पुलिसकर्मी

एसपी नवनीत कॉवत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जिन कर्मचारियों का कार्यकाल पूरा हो चुका है या जो तबादले के मानदंडों में आते हैं, उन्हें कोई भी 'संरक्षण' नहीं मिलेगा। इसके बावजूद कई कर्मचारी अपने 'गॉडफादर' नेताओं और प्रभावशाली लोगों के पास पहुंचे, ताकि अपनी जगह पर बने रह सकें। हालांकि एसपी ने स्वयं तबादलों में सक्रिय भूमिका निभाई, तीन दिनों तक लगातार अधिकारियों और कर्मचारियों से संवाद किया, उनकी बात भी सुनी - लेकिन जिनकी नियुक्ति लंबे समय से एक ही जगह पर थी, उन्हें स्पष्ट रूप से इशारा मिल गया कि अब बदलाव तय है। जनप्रतिनिधियों को भी मिला स्पष्ट संदेश

एसपी नवनीत कॉवत ने यह भी संदेश दिया है कि वे किसी जनप्रतिनिधि की अनुचित सिफारिश नहीं मानेंगे। यह रुख बीड जिले के पुलिस प्रशासन में एक नई पारदर्शिता और जवाबदेही का संकेत माना जा रहा है। एसपी द्वारा उठाए गए इस कदम की चर्चा पूरे जिले में जोरों पर है, और इसे प्रशासनिक दृष्टि से एक साहसी तथा अनुकरणीय पहल बताया जा रहा है।

बडे मन का बच्चा

सुपर स्टार रजनीकांत की गोद मे बैठा यह बच्चा तमिलनाडु मे ईमानदारी की मिसाल बन गया ।
मोहम्मद यासीन को ५० हजार रुपये सडक पर मिले
वह सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और थानेदार को रकम देकर कहा -
यह रूपये मुझे सड़क पर मिले है
जिसके भी हो ढूंढ़कर लौटा दे'
थानेदार ने बच्चे से पूंछा की ये पैसे उसने क्यों नही रखे
तो यासीन ने जवाब दिया ये पैसा किसी की खून पसीने की कमाई का है
मेरा नही है
तो मैं उसे अपने पास कैसें रख सकता हूँ।
थानेदार ने उसकी ईमानदारी देखकर यासीन से पूछा
अपनी कोई ख्वाहिश बताएं जिसको हम पूरा कर सकें
यासीन ने झट से साउथ के सुपर स्टार रजनीकांत से मिलने की ख्वाहिश बताई
उसको रजनी से मिलवाया गया और रजनीकांत ने बच्चे के माँ बाप से वादा किया कि इस बच्चे की पढाई का पूरा खर्चा वह उठाएंगे,
दुनियां में जिस महंगे से महंगे स्कूल/कॉलेज में ये पढ़ाई करना चाहे कर सकता है।
अब से इस बच्चे को मेरे सगे बेटे जैसा दर्जा देता हूँ मैं।

धुले विश्रामगृह में मिले १.८४ करोड़ की जांच SIT से करवाई जाएगी-मुख्यमंत्री फडणवीस

ठेकेदारों से १५ करोड़ वसूलने की थी योजना: सांसद संजय राउत

- रिपोर्ट: जमीर काज़ी, मुंबई

मुंबई, २२ मई:

विधानमंडल की अनुमान समिति के धुले दौरे के दौरान सरकारी विश्रामगृह के कमरे में १.८४ करोड़ रुपये नकद बरामद होने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई है। इस प्रकरण पर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस संपूर्ण मामले की जांच एसआईटी (विशेष जांच दल) से कराए जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जांच से यह स्पष्ट होगा कि यह राशि किस उद्देश्य से और किसके लिए जमा की गई थी।

यह राशि विधायक अर्जुन खोतकर, जो अनुमान समिति के अध्यक्ष हैं, उनके पीए कदम के कमरे से बरामद की गई। पूर्व विधायक अनिल गोटे ने इस मामले का खुलासा करते हुए आरोप लगाया कि यह रकम अर्जुन खोतकर को ही दी जानी थी।

इस प्रकरण में ठाकरे गुट के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शिंदे गुट को आड़े हाथों लेते हुए ईडी और सीबीआई जांच की मांग की है। राउत ने कहा कि अनुमान समिति का उद्देश्य राज्य सरकार की विकास योजनाओं का मूल्यांकन करना है, लेकिन धुले जिले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है।

कथित रूप से खोतकर ने ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की धमकी दी, जिसके बाद एक ठेकेदार ने १५ करोड़ रुपये जुटाने की जिम्मेदारी ली। तीन दिनों में ५ करोड़ की वसूली हो चुकी थी और शेष १० करोड़ आने बाकी थे, ऐसा संजय राउत ने दावा किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अब खोतकर को बचाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं, जबकि यह भ्रष्टाचार उजागर होने का अवसर है।

संजय राउत ने आगे कहा कि पिछले एक साल में अनुमान समिति ने किन-किन जिलों का दौरा किया और वहां क्या हुआ - इसकी भी जांच होनी चाहिए।

राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट) के विधायक रोहित पवार ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। एक्स (पूर्व ट्विटर) पर उन्होंने लिखा, जब कोई कार्य असाधारण हो, तो उसके लिए पुरस्कार स्वरूप नकद धनराशि दी जाती है। क्या इस अनुमान समिति ने कोई विशेष कार्य किया था कि करोड़ों रुपये इकट्ठा किए जा रहे थे? उन्होंने व्यंग्यपूर्वक कहा कि जैसे ही गोटे साहब अचानक कमरा नंबर १०२ में पहुंचे, समिति की 'महान उपलब्धियों' पर और उनके 'इनाम' पर पानी फिर गया।

मुख्यमंत्री की डखढ जांच की घोषणा के बाद अब राजनीतिक हलकों में यह बहस तेज हो गई है कि क्या इस मामले में शिंदे गुट के बड़े नेता और महायुती सरकार के अन्य घटक भी जांच के घेरे में आएंगे।

धुले रेस्ट हाउस में नकदी मिलने के मामले में मूल खबर यही-विधानमंडल कक्ष अधिकारी निलंबित

- धुले, २२ मई

धुले जिले में विधानमंडल की अनुमान समिति के दौरे के दौरान रेस्ट हाउस के कमरे में १.८४ करोड़ रुपये नकद मिलने के मामले ने जहां महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है, वहीं अब इस प्रकरण में प्रशासनिक कार्रवाई की शुरुआत भी हो गई है।

विधानमंडल के संशयास्पद कक्ष अधिकारी किशोर पाटील को निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई की पुष्टि विधानपरिषद के सभापति प्रो. राम शिंदे ने की है। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी घटना की जांच के लिए एक समिति गठित की जा रही है, जो यह स्पष्ट करेगी कि नकदी कहां से आई, क्यों रखी गई और इसमें किन अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है।

उल्लेखनीय है कि यह नकदी अनुमान समिति के अध्यक्ष आ. अर्जुन खोतकर के पीए के कमरे से बरामद की गई थी, जिसे लेकर विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। अब इस कार्रवाई से मामले ने नया मोड़ ले लिया है।

ड्रोन बंदी से किसानों की परेशानी, खेती के लिए निर्णय पर पुनर्विचार की मांग

- बीड़ से विशेष संवाददाता

बीड: केंद्र सरकार द्वारा सभी प्रकार के ड्रोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए जाने से उन किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जो कृषि कार्यों के लिए ड्रोन का उपयोग कर रहे थे। इस पृष्ठभूमि में कामगार नेता राजकुमार घायाळ ने जिला प्रशासन से भेंट कर यह मांग की कि खेती के लिए इस प्रतिबंध पर पुनर्विचार किया जाए।

इस विषय में अधिक जानकारी देते हुए राजकुमार घायाळ ने बताया कि जिले के कई किसानों ने अपनी फल बागानों में मृग बहार के लिए वृक्षों को तनाव में रखा था, ताकि बेहतर फसल प्राप्त हो सके। लेकिन अचानक आए पूर्व-मौसमी बारिश के कारण यह तनाव टूट गया, जिससे पौधों को तात्कालिक फवारणी (कीटनाशक या पोषक छिड़काव) की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है।

विशेषज्ञों के अनुसार, ड्रोन द्वारा की जाने वाली फवारणी अधिक प्रभावी मानी जाती है। लेकिन ड्रोन पर लगी रोक के चलते किसान इसे प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनकी परेशानियाँ बढ़ गई हैं। इस स्थिति को देखते हुए राजकुमार घायाळ ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि केवल खेती के उद्देश्य से ड्रोन प्रतिबंध पर पुनर्विचार किया जाए और किसानों को राहत प्रदान की जाए।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

अजित पवार की पार्टी 'गुंडों की टोली', तो एकनाथ शिंदे हैं 'लुटेरों के सरगना' : कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ का तीखा हमला

– रिपोर्ट: जमीर काज़ी, मुंबई

मुंबई, २२ मई:

राज्य में लगातार सामने आ रहे आपराधिक मामलों में अजित पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोगों की संलिप्तता पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अजित पवार की पार्टी गुंडों की टोली बन चुकी है, जबकि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लुटेरों की टोली के सरगना हैं।

गांधी भवन में आयोजित पत्रकार परिषद में गुरुवार को बोलते हुए सपकाळ ने राज्य सरकार और उसकी कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीड के मस्साजोग की घटना, पुणे के पोर्श कार ड्रंक एंड ड्राइव प्रकरण, कोयता गैंग का मामला, शेल्टर होम की आड़ में युवतियों का यौन शोषण करने वाला शंतनु कुकडे, उसका साथी दीपक मानकर (राष्ट्रवादी कांग्रेस), और वैष्णवी हगवणे को दहेज के लिए प्रताड़ित कर हत्या करने वाला राजेंद्र हगवणे – ये सभी आरोपी राष्ट्रवादी कांग्रेस (अजित पवार गुट) से जुड़े हैं।

उन्होंने सवाल उठाया कि, इन सभी अपराधियों का अजित दादा की पार्टी से संबंध होना संयोग है या पार्टी की शरणस्थली बन चुकी है? उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि ये गुंडे इसलिए बेलगाम हैं क्योंकि सत्ता उनके साथ है और सरकार ने जैसे इन अपराधियों का पालकत्व ले लिया है।

राज्य महिला आयोग की नाकामी पर नाराज़गी जताते हुए उन्होंने कहा कि अगर महिला आयोग ने समय पर संज्ञान लिया होता, तो वैष्णवी की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन आयोग की अध्यक्ष को महिलाओं की सुरक्षा से अधिक, राजनीतिक चमक-दमक में रुचि है, जिससे राज्य में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं।

सपकाळ ने कहा कि भाजपा-शिंदे-अजित पवार गुट की महायुती सरकार भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी है और इसमें शामिल मंत्री और विधायक केवल लूट में लगे हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि धुले दौरे के दौरान, विधानसभा की बजट समिति के प्रमुख विधायक अर्जुन खोतकर के पीए के कमरे से लगभग २ करोड़ रुपये नकद बरामद हुए। उन्होंने इसे सरकार की लूट का पुख्ता प्रमाण बताया और कहा कि यह रकम ठेकेदारों से वसूली गई थी।

मुख्यमंत्री फडणवीस से की गिरफ्तारी की मांग

सपकाळ ने मांग की कि यदि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हैं, तो वे खोतकर और उनके पीए पर तुरंत मामला दर्ज करवाकर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। साथ ही, शिंदे गुट के सभी विधायकों की जांच लाचलुचपत विभाग (-उइ), ईडी और इनकम टैक्स विभाग से कराई जाए।

कृषि संकट पर सरकार को घेरा

राज्य में हाल ही में आए अवकाळी बारिश (असमय वर्षा) से हजारों-लाखों हेक्टेयर फसलें और बाग़बानी को नुकसान हुआ है, खासकर प्याज उत्पादक किसानों को बड़ा झटका लगा है। लेकिन सरकार न तो मदद कर रही है और न ही पंचनामे किए जा रहे हैं। इसके अलावा, खरीफ सीजन सर पर है, और राज्य में नकली बीज और खाद का बड़ा नेटवर्क सक्रिय हो गया है, यह आरोप भी सपकाळ ने लगाया।

बीड शहर की ज्वलंत समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस का शिष्टमंडल नगर परिषद में सक्रिय

– बीड, २२ मई (प्रतिनिधि)

बीड शहर में बढ़ती नागरिक समस्याओं के तात्कालिक समाधान की मांग को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस (अजित पवार गुट) के शिष्टमंडल ने गुरुवार (२२ मई) को नगर परिषद की मुख्याधिकारी नीता अंधारे से भेंट कर विस्तृत ज्ञापन सौंपा। यह शिष्टमंडल युवा नेता डॉ. योगेश क्षीरसागर के नेतृत्व में नगर परिषद कार्यालय पहुंचा, जिसमें कई पूर्व नगरसेवक भी शामिल थे।

ज्ञापन में कहा गया है कि शहर में मानसून पूर्व स्वच्छता, नाला सफाई, पथदीपों की मरम्मत, सड़कों की जर्जर स्थिति, जलापूर्ति की अव्यवस्थित व्यवस्था, अधूरे बाजार प्रांगण व आरोग्य सेवाओं की बदहाली जैसी अनेक समस्याएं गंभीर रूप से नागरिकों को प्रभावित कर रही हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु जल्द से जल्द ठोस कार्ययोजना लागू की जानी चाहिए।

स्वच्छता और जलनिकासी पर विशेष जोर:

शिष्टमंडल ने बताया कि शहर के कई मुख्य नाले कचरे से पूरी तरह जाम हो चुके हैं, जिससे मच्छरों की संख्या, दुर्गंध और स्वास्थ्य संबंधी खतरे बढ़े हैं। इन नालों की यंत्रों की मदद से तात्कालिक सफाई कराई जाए। साथ ही, स्वच्छता के लिए घंटागाड़ी, जेसीबी, और कचरा संकुचन यंत्र (कम्पैक्टर) खरीदे जाएं।

पथदिवे और ऊर्जा समाधान:

शहर के कई इलाकों में स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी हैं, तो कुछ क्षेत्रों में दिन में भी लाइट जल रही हैं। हायमास्ट लाइटें भी खराब हालत में हैं। इनकी त्वरित मरम्मत के साथ-साथ सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाकर मिनी हायमास्ट लाइट, श्मशानभूमि में प्रकाश व्यवस्था तथा नगर परिषद भवन पर सौर प्रकल्प स्थापित करने की मांग की गई।

जलापूर्ति योजनाएं और वेतन मुद्दे:

जलापूर्ति विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को समय पर वेतन दिया जाए। माजलगांव और बिंदुसरा परियोजना की सहायता से नई जल योजनाएं तैयार कर सरकार को प्रस्तुत की जाएं। श्रीरामनगर की पुरानी पानी टंकी के स्थान पर नई टंकी का निर्माण किया जाए। साथ ही, अवैध नल कनेक्शनों को नियमित कर कर प्रणाली में लाया जाए।

बुनियादी निर्माण कार्य और सौंदर्यीकरण: शिष्टमंडल ने यशवंत नाट्यगृह और डॉ. आंबेडकर सांस्कृतिक भवन की मरम्मत, प्रमुख चौकों का सौंदर्यीकरण, नई सब्जी मंडी और दुकानों का कार्य पूर्ण कर शुरू करने, सड़कों पर गड्ढे भरने, सीमेंट सड़क की मरम्मत, बेघर महिलाओं के लिए आश्रय गृह और नए श्मशानभूमि के निर्माण की मांग रखी।

स्वास्थ्य और कर वसूली क्षेत्र की समस्याएं: आरोग्य विभाग के मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपर्याप्त हैं। नए केंद्रों के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए, विशेष रूप से पेठ बीड और शाहूनगर क्षेत्र के लिए। कर वसूली की दक्षता बढ़ाने हेतु डिजिटल माध्यम अपनाते हुए गूगल पे जैसे ऐप विकसित किए जाएं। साथ ही, व्यवसायिक दुकानों का नया पंजीकरण कर नगर परिषद की आय बढ़ाई जाए।

वृक्षारोपण और अग्निशमन सेवाएं:

बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए अग्निशमन वाहनों की संख्या बढ़ाई जाए, एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) के लिए भूमि तय की जाए, और सड़कों के दोनों ओर वृक्षारोपण किया जाए। मियावाकी पद्धति से घने वृक्षारोपण की भी मांग की गई।

यह संपूर्ण ज्ञापन राष्ट्रवादी कांग्रेस के युवा नेता डॉ. योगेश क्षीरसागर के नेतृत्व में प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर पूर्व नगरसेवक बाबुराव दुधाळ, गणेश वाघमारे, भीमराव वाघचौरे, नरसिंग नाईकवाडे, सादेक जमा, भास्करराव जाधव, इकबाल शेख, विकास जोगदंड, प्रेम चांदणे, सतिश पवार, राणा चौहान, मुन्ना इनामदार, रवींद्र कदम, शुभम धुत, जैतुल्ला खान, सहित नागरिक, नगर परिषद के सभी विभागों के प्रमुख और पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे।

परिवहन विभाग की जमीनों का होगा पीपीपी मॉडल पर विकास-परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

– विशेष प्रतिनिधि, मुंबई

मुंबई, २२ मई:

राज्यभर में परिवहन विभाग के पास मौजूद कुल ४३ जमीनों में से मुंबई की ४ प्रमुख जगहों पर अवैध कब्जे हो चुके हैं, जबकि १५ स्थानों पर परिवहन कार्यालय किराए की जगहों पर संचालित हो रहे हैं। भविष्य में इन शासकीय जमीनों पर कब्जा न हो, इसके लिए परिवहन विभाग को इन सभी जमीनों का विकास पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के तहत करने के प्रयास करने चाहिए – ऐसा निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने विभागीय समीक्षा बैठक में दिया।

मंत्री सरनाईक ने कहा कि मोटार परिवहन विभाग की सभी ४३ जमीनों की जानकारी अद्यतन की जाए, उनकी वर्तमान स्थिति, ७/१२ और ८-अ जैसे दस्तावेज तैयार कर यह जानकारी परिवहन आयुक्त कार्यालय को सौंपी जाए। जिन जगहों पर अतिक्रमण हुआ है, वहां कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से अतिक्रमण हटाया जाए।

बैठक में जानकारी दी गई कि मुंबई के घाटकोपर (रमाबाई नगर) की ७ एकड़ जमीन, वडाला, जुहू और अंधेरी की जमीनें झोपड़पट्टी धारकों द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गई हैं। मंत्री ने इस बात पर खेद जताया कि वर्षों तक विभाग का ध्यान इन अतिक्रमणों की ओर नहीं गया।

उन्होंने निर्देश दिया कि आगे ऐसा दोबारा न हो, इसके लिए सभी सरकारी जमीनों पर घेरा (कुंपण) लगाया जाए और जल्द से जल्द इन जमीनों के विकास के लिए ठोस योजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि इन जमीनों का विकास पीपीपी मॉडल पर किया जाए, जिसमें अगले ५० वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग के लिए आवश्यक कार्यालय, टेस्टिंग ट्रैक और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएं।

२० जून को लिया जाएगा अंतिम निर्णय

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि विभाग के स्वामित्व वाली जमीनों का निरीक्षण संबंधित अधिकारी करें। इसके लिए समिति गठित कर प्रत्येक जमीन की अलग-अलग फाइल तैयार की जाए। साथ ही आगामी १५ दिनों में जमीन से संबंधित सभी दस्तावेजों की समीक्षा और प्रमाणिकता की प्रक्रिया पूर्ण की जाए, ताकि २० जून को होने वाली अगली बैठक में इन जमीनों के विकास को लेकर अंतिम निर्णय लिया जा सके।

बैठक में परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, सहसचिव राजेंद्र होळकर, अतिरिक्त आयुक्त भरत कळसकर सहित सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी उपस्थित थे। मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए 'एस्टेट ऑफिसर' और 'कानूनी सलाहकार' की नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए।

आधार में गलत जानकारी दर्ज है? तुरंत करें अपडेट, वरना हो सकती है जेल और जुर्माना!

नई दिल्ली, २२ मई २०२५ (एढत इहरीरीं कळपवळ ढशरा): आधार कार्ड भारत के नागरिकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहचान पत्र बन चुका है। इसका उपयोग बैंकिंग, सिम कार्ड प्राप्त करने, राशन और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने जैसे अनेक कार्यों में किया जाता है। हालांकि, यदि आधार कार्ड में गलत जानकारी दर्ज है, तो यह कानूनी रूप से गंभीर अपराध माना जाता है और इसके लिए जेल और जुर्माने की सजा भी हो सकती है।

जानबूझकर गलत जानकारी देने पर सख्त सजा का प्रावधान

अगर आपके आधार में नाम, जन्मतिथि, पता या मोबाइल नंबर जैसी कोई भी जानकारी गलत दर्ज है, तो उसे तत्काल सही कराना बेहद जरूरी है। जानबूझकर गलत जानकारी देना या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जानकारी दर्ज कराना आधार अधिनियम २०१६ की धारा ३८ के तहत अपराध है। इस अपराध पर तीन साल तक की जेल और १०,००० रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

धारा ३९ में भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान

आधार अधिनियम की धारा ३९ के तहत, अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की आधार जानकारी उसकी अनुमति के बिना साझा करता है या उपयोग करता है, तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

किन मामलों में होती है सजा?

अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने आधार में गलत जानकारी जैसे कि नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर दर्ज करता है।

अगर कोई व्यक्ति किसी और की पहचान का दुरुपयोग करके फर्जी आधार कार्ड बनवाता है।

ये सभी कार्य अपराध की श्रेणी में आते हैं और दोषी पाए जाने पर सजा दी जा सकती है।

सजा से कैसे बचें?

आधार कार्ड में केवल सही और प्रमाणिक जानकारी ही दर्ज करें। किसी भी जानकारी को छिपाने, बदलने या गलत जानकारी देने से बचें।

किसी अन्य व्यक्ति की पहचान का दुरुपयोग न करें। आधार का उपयोग बेहद सावधानी और ज़िम्मेदारी से करें।

यह भी जानें:

कैसे पता करें कि आपके आधार से कौन सा मोबाइल नंबर जुड़ा है

कहीं आपके आधार का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा? ऐसे करें ऑनलाइन जांच

आधार के लिए चेहरा पहचानने वाली तकनीक मोबाइल ऐप से भी संभव

५ और १५ वर्ष की आयु पर बच्चों का आधार अपडेट कराना अनिवार्य

अगर वोटर कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो क्या आयोग के सामने पेश होना ज़रूरी है?

भूख, हसरत और आत्मग्लानि की अनकही दास्तान:

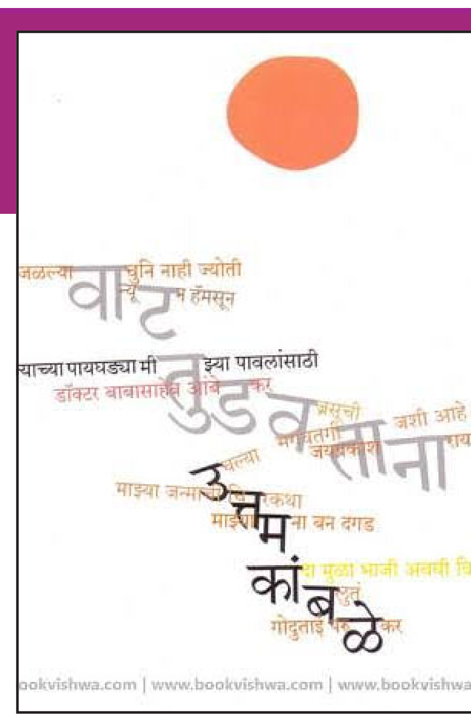

वाट तुडवताना

का एक मार्मिक अध्याय

– किताब समीक्षा ।

लेखक: उत्तम कांबळे ।

प्रकाशक: मनोविकास, पुणे

: मराठी साहित्य में आत्मकथात्मक लेखन की सशक्त कड़ी 'वाट तुडवताना' में वरिष्ठ पत्रकार उत्तम कांबळे ने अपनी गरीबी से भरी पृष्ठभूमि और एक पत्रकार की हैसियत से पहली बार किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का जो अनुभव साझा किया है, वह रसभरा नहीं, बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाला है।

कांबळे बताते हैं कि कैसे एक राजनीतिक नेता द्वारा आयोजित प्रेस बैठक में उन्हें पहली बार काजू, बादाम, सेब, मटन-चिकन फ्राय, बिरयानी और आइसक्रीम जैसे व्यंजन खाने को मिले। स्वाद की यह नई दुनिया उन्हें रोमांचित करती है। लेकिन यह आनंद क्षणिक है – बचपन की भूख, गरीबी, मां की लाचारी, शराबी पिता की हिंसा और अंधकारमय अतीत उनके सामने छा जाता है। जब सब पत्रकार शराब के गिलास उठाते हैं, तो कांबळे भी ललचते हैं, लेकिन अण्णा और अक्का की स्मृतियाँ उन्हें रुकने पर मजबूर कर देती हैं।

दारू का मोह झुर्र की तरह झटक दिया, वे लिखते हैं।

व्यंजन पर टूट पड़ने के इस अनुभव में लेखक यह नहीं छिपाते कि उन्होंने बकासुर की तरह खाया। पाचन की याचना करते हुए ईश्वर से विनती करते हैं कि हे प्रभु, मेरे पेट में फूड क्रशर ही लगा दो! लेकिन फिर जैसे ही रात होती है और वे खाना पचाने की कोशिश में बोर्डिंग हाउस लौटते हैं, उनका शरीर ही नहीं, अंतरात्मा भी भारी हो चुकी होती है।

अकेले चलते-चलते, वे उस मिट्टी के घर में लौट जाते हैं, जहाँ दस पैसे की दाल से बनी आमटी में डूबी भाकरी और भावनाओं में लिपटी अक्का उन्हें याद आती है। तब वे निर्णय लेते हैं – मैं अब राक्षसों की तरह भोजन नहीं करूंगा। मैं खाने के लिए नहीं, जीने के लिए खाऊंगा।

इस अंश में न सिर्फ एक पत्रकार का अनुभव है, बल्कि यह उस विशाल वर्ग की व्यथा है जो गरीबी से निकलकर व्यवस्था का हिस्सा बनता है और भोग की चकाचौंध में कभी खुद को ही खो बैठता है। कांबळे के लेखन की यही खूबी है – वे खुद को सामने रखते हैं, अपनी भूख, लालच, लोभ और आत्मग्लानि को भी। यही ईमानदारी उन्हें बड़ा बनाती है।

'वाट तुडवताना' केवल आत्मकथा नहीं, यह सामाजिक विषमता, मानसिक संघर्ष और संवेदनशील आत्मनिरीक्षण का दस्तावेज है। यह पुस्तक पढ़ते हुए पाठक सिर्फ लेखक की कहानी नहीं, अपनी भी कई भूखें पहचानता है।

दैनिक तामीर डेस्क

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com